



देश | समाज | राजनीति | अर्थव्यवस्था | शिक्षा | संस्कृति | दुनिया

शह नक्बर में भारत यात्रा कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टों में 23 से 25 नवंबर की संभावित तारीखों का उल्लेख किया गया है, लेकिन दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम की तारीखें अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई हैं। यह यात्रा शाह का पहला आधिकारिक द्विपक्षीय विदेश दौरा हो सकती है। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में भाग लेने के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क गए थे। वह यात्रा बहुपक्षीय मंच से जुड़ी थी, इसलिए प्रस्तावित भारत दौरे को उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा के रूप में देखा जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह को पदभार संभालने के बाद आपसी सहमति से तय समय पर भारत आने का निमंत्रण दिया था। प्रस्तावित यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच और हवाई संपर्क पर हो सकती है चर्चा भारत और नेपाल के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दे लंबे समय से चर्चा में हैं। प्रस्तावित दौरे के दौरान सीमा संबंधी विवादों, नेपाल के लिए भारत के रास्ते हवाई संपर्क, व्यापार में असंतुलन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बातचीत हो सकती है। विकास परियोजनाओं पर भी नजर मीडिया रिपोर्टों में नेपाल पुलिस अकादमी, दारचुला में पुल, भैरहवा में एकीकृत जांच चौकी और महाकाली नदी पर मोटर वाहन आवागमन के लिए पुल जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, दोधारा चंदनी में एकीकृत जांच चौकी, लेनेअर अरुण जलविद्युत परियोजना तथा भारत के सिलीगुड़ी क्षेत्र से नेपाल के झापा तक प्रस्तावित पेट्रोलियम पाइपलाइन के निर्माण से जुड़ी गतिविधियों पर भी चर्चा की संभावना जताई गई है। इन परियोजनाओं का महत्व केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं है। क्हेतर सीमा ढांचा, ऊर्जा सहयोग और परिवहन सुविधाएं दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और लोगों के आवागमन को गति दे सकती हैं।

सम्पादकीय

मतदाता सूची की शुद्धता के साथ हर नागरिक का मताधिकार भी जरूरी

भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com

भारत में लोकतंत्र की मजबूती केवल चुनाव कराने से नहीं, बल्कि इस बात से सुनिश्चित होती है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को बिना किसी बाधा के मतदान का अवसर मिले। मतदाता सूची इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। सूची में सही नाम, सही पता और पात्रता का सटीक विवरण चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। इसलिए मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (र) केवल प्रशासनिक कवायद नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों, चुनावी पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता



सूची को अद्यतन करना, अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना, स्थान बदल चुके मतदाताओं के विवरण में आवश्यक सुधार करना और पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है। समय के साथ लोगों के निवास स्थान बदलते हैं, नए नागरिक मतदान की आयु प्राप्त करते हैं और मृत्यु या अन्य कारणों से पुराने विवरणों में संशोधन की जरूरत पड़ती है। इन परिस्थितियों में मतदाता सूची का नियमित सत्यापन आवश्यक है। लेकिन इस प्रक्रिया की सफलता केवल गलत प्रविष्टियां हटाने से नहीं, बल्कि पात्र मतदाताओं के नाम सुरक्षित रखने से भी मापी जानी चाहिए। प्रक्रिया की पारदर्शिता ही भरोसे की पहली शर्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि पात्र नागरिकों के नाम छूटने की स्थिति में उन्हें न्याय पाने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है या नहीं। यदि किसी मतदाता का नाम मसौदा सूची में नहीं मिलता, तो उसे यह जानकारी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए कि नाम शामिल न होने का कारण क्या है और उसे सुधारने के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनानी होगी। निर्वाचन आयोग का कहना है कि पुनरीक्षण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल रखना तथा मृत, दोहरी या अपात्र प्रविष्टियों को हटाना है। यह उद्देश्य चुनावी शुचिता के लिए आवश्यक है। लेकिन किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता उसके घोषित उद्देश्य के साथ—साथ उसके वास्तविक क्रियान्वयन से तय होती है। इसलिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधित करने के प्रत्येक निर्णय में निर्धारित प्रक्रिया, सत्यापन और संबंधित नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए। मतदाता सूची में नाम शामिल करने या आवश्यक सुधार के लिए निर्वाचन आयोग की निर्धारित आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है। नागरिकों को अपने नाम की स्थिति जांचने, संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने और निर्धारित समय सीमा में दावा या आपत्ति दर्ज कराने की सुविधा मिलनी चाहिए। विशेष रूप से उन लोगों के लिए सहायता व्यवस्था प्रभावी होनी चाहिए, जिन्हें डिजिटल माध्यमों, दस्तावेजों या प्रशासनिक कार्यालयों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। कमजोर और वंचित वर्गों के सामने विशेष चुनौतियां भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी नागरिकों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जाने वाले प्रवासी श्रमिक, किराये के मकानों में रहने वाले परिवार, बुजुर्ग, दिव्यांगजन और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक दस्तावेजों तथा पते के सत्यापन के दौरान अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। कई बार स्थान परिवर्तन, दस्तावेजों में नाम की वर्तनी का अंतर या जानकारी के अद्यतन में देरी जैसी सामान्य परिस्थितियां भी परेशानी पैदा कर सकती हैं। ऐसी स्थितियों में प्रशासनिक सुविधा के नाम पर नागरिकों पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। दूसरी ओर, किसी भी दावे की जांच किए बिना उसे स्वीकार कर लेना भी उचित नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट, समयबद्ध और मानवीय हो। मताधिकार केवल एक औपचारिक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिक और शासन के बीच लोकतांत्रिक संबंध का महत्वपूर्ण आधार है। किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं होना उसके चुनाव में भाग लेने के अवसर को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसी शिकायतों को केवल आंकड़ों या तकनीकी त्रुटियों के रूप में देखने के बजाय उनके संभावित मानवीय प्रभाव को भी समझना चाहिए। राजनीतिक आरोपों से अलग हो तथ्यपरक जांच-पू का लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप—प्रत्यारोप सामने आए हैं। कुछ विपक्षी दलों ने पात्र मतदाताओं के नाम हटाए जाने की आशंका जताई है, जबकि निर्वाचन आयोग पुनरीक्षण को मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया बताते है।

स्वच्छ परिवहन का लक्ष्य:इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ें, लेकिन सार्वजनिक बसें भी मजबूत हों



भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com

शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण, सड़कों पर वाहनों का दबाव, ईंधन की खपत और जलवायु परिवर्तन की चुनौती भारत के सामने परिवहन व्यवस्था को नए रिस्रे से विकसित करने की आवश्यकता रखती है। इलेक्ट्रिक वाहन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर उभरे हैं। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह बिजली से चलने वाले वाहन अपनाने से सड़क पर होने वाले प्रत्यक्ष उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन क्या केवल इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ा देने से शहरों की हवा स्वच्छ हो जाएगी? इसका उत्तर हैकूनहीं। स्वच्छ परिवहन का लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब वाहन तकनीक के साथ सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, चार्जिंग सुविधाओं और बैटरी के सुरक्षित निपटान पर भी समान ध्यान दिया जाए। परिवहन और प्रदूषण की चुनौती भारत के बड़े शहरों में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात जाम,

ईंधन की खपत और प्रदूषण की समस्या को जटिल बनाती है। सड़क परिवहन से निकलने वाले धुएं और अन्य प्रदूषकों का प्रभाव स्थानीय वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। हालांकि, वायु प्रदूषण के सभी स्रोत परिवहन से संबंधित नहीं हैं। निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन, धूल, कचरा जलाना और अन्य स्रोत भी इसमें योगदान करते हैं। इसलिए प्रदूषण नियंत्रण के लिए समग्र नीति की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहनों का एक प्रमुख लाभ यह है कि वे चलते समय पारंपरिक ईंधन की तरह धुआं नहीं छोड़ते। इससे व्यस्त सड़कों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थानीय प्रदूषण कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके अतिरिक्त, लक्ष्य तभी हासिल होगा, जब वाहन तकनीक के साथ सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा उत्पादन, चार्जिंग सुविधाओं और बैटरी के सुरक्षित निपटान पर भी समान ध्यान दिया जाए। परिवहन और प्रदूषण की चुनौती भारत के बड़े शहरों में निजी वाहनों की बढ़ती संख्या यातायात जाम,

अपनाने के साथ चार्जिंग नेटवर्क भी जरूरी इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता केवल उनकी खरीद कीमत पर निर्भर नहीं करती। उपभोक्ताओं के लिए यह भरोसा भी जरूरी है कि यात्रा के दौरान चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी और वाहन को दोबारा चार्ज करने में अत्यधिक समय या खर्च नहीं लगेगा। यदि चार्जिंग केंद्र सीमित हों, तो लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों और उन लोगों को विशेष परेशानी हो सकती है जिनके पास घर पर चार्जिंग की व्यवस्था नहीं है। सरकारों और स्थानीय निकायों को आवासीय क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्किंग स्थलों, कार्यालयों, राजमार्गों और प्रमुख परिवहन केंद्रों पर योजनाबद्ध ढंग से चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना चाहिए। चार्जिंग सुविधाओं का वितरण केवल संपन्न इलाकों तक सीमित न रहे। छोटे शहरों, बाहरी बस्तियों और आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों तक भी इनकी पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके साथ बिजली वितरण व्यवस्था की क्षमता, चार्जिंग केंद्रों की सुरक्षा, पारदर्शी शुल्क और तकनीकी मानकों पर ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन नीति तभी प्रभावी होगी, जब आम नागरिक के लिए वाहन चलाना सुविधाजनक और आर्थिक रूप से व्यावहारिक बने। सार्वजनिक बसेंरूप प्रदूषण घटाने का व्यापक माध्यम स्वच्छ परिवहन की चर्चा में निजी इलेक्ट्रिक कारों और दोपहिया वाहनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि सार्वजनिक बसों की भूमिका कहीं अधिक व्यापक हो सकती है। एक अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ यात्रा करने की सुविधा देती है। इससे निजी वाहनों पर निर्भरता, सड़क पर

वाहनों की संख्या और पार्किंग की आवश्यकता कम करने में मदद मिल सकती है। यदि शहरों में पर्याप्त बसें, नियमित समय-सारणी, सुरक्षित बस स्टॉप, सुगम टिकट व्यवस्था और अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुविधाजनक संपर्क उपलब्ध हों, तो अधिक लोग निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल बसों को इलेक्ट्रिक बना देना पर्याप्त नहीं होगा। बसों की संख्या, मार्गों की उपयोगिता, संचालन की नियमितता, रखरखाव स्थलों, यात्रियों की सुख्या पर भी ध्यान देना होगा। महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाना भी आवश्यक है। सुविधाजनक और भरोसेमंद बस सेवा नागरिकों को निजी वाहन पर निर्भर रहने की मजबूरी से बाहर निकाल सकती है। बिजली के स्रोत और बैटरी प्रबंधन पर ध्यान इलेक्ट्रिक वाहनों के पर्यावरणीय लाभ इस बात से भी जुड़े हैं कि उन्हें चलाने के लिए बिजली किस प्रकार उत्पन्न की जा रही है। यदि बिजली उत्पादन में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी अधिक है, तो वाहन के उपयोग से होने वाले कुल उत्सर्जन में कमी का आकलन पूरे ऊर्जा तंत्र को ध्यान में रखकर करना होगा। इसलिए स्वच्छ परिवहन और स्वच्छ ऊर्जा को अलग-अलग नीतिगत विषयों के रूप में नहीं देखा जा सकता। सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, बिजली ग्रिड की मजबूती और ऊर्जा भंडारण की बेहतर व्यवस्था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के पर्यावरणीय लाभ बढ़ाने

में सहायक हो सकती है। बैटरी का जीवनकाल समाप्त होने के बाद उसका सुरक्षित पुनर्चक्रण भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। बैटरियों में उपयोग होने वाली सामग्री का उचित प्रबंधन नहीं किया गया, तो मिट्टी, पानी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचने का खतरा हो सकता है। निर्माताओं, पुनर्चक्रण कंपनियों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के बीच स्पष्ट जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बैटरी संग्रह, सुरक्षित परिवहन, सामग्री की पुनर्प्राप्ति और पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना दीर्घकालीन नीति का हिस्सा होना चाहिए। संपादकीय दृष्टिकोणरूप तकनीक के साथ परिवहन व्यवस्था में बदलाव भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहन देना ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी विकास और प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर भी नीति की सफलता केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री या पंजीकरण की संख्या से नहीं मापी जानी चाहिए। यह देखना भी आवश्यक है कि शहरों की वायु गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कितना बढ़ा, चार्जिंग सुविधाएं कितनी सुलभ हुईं और बैटरियों का निपटान पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, नगर निकायों और परिवहन विभागों के बीच समन्वय जरूरी है। शहरों की योजना बनाते समय पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों, बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। फुटपाथों और साइकिल मार्गों की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और मिश्रित भूमि उपयोग जैसी व्यवस्था भी निजी वाहनों पर निर्भरता कम कर सकती

है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। यदि आयातित वस्तुएं कम कीमत पर बड़ी मात्रा में घरेलू बाजार में पहुंचती हैं, तो कुछ भारतीय उत्पादकों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ सकता है। इसका प्रभाव विशेष रूप से उन छोटे उद्योगों पर पड़ सकता है, जिनकी उत्पादन लागत अधिक है या जिनके पास आधुनिक तकनीक, सस्ता वित्त और बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधाएं सीमित हैं। इसलिए किसी भी शुल्क रियायत का आकलन पूरे औद्योगिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। यह देखना जरूरी है कि उससे उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ घरेलू उत्पादन, निवेश और रोजगार पर पड़ने वाले संभावित दबाव के मुकाबले कितना टिकाऊ है। इसका अर्थ यह नहीं कि घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से हमेशा बचाकर रखा जाए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नवाचार, गुणवत्ता और दक्षता को प्रोत्साहित

है। नीतियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और छोटे परिवहन संचालकों की जरूरतों को भी शामिल करना चाहिए। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहन उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका लाभ व्यापक सामाजिक हित, सार्वजनिक परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण के लक्ष्यों के साथ संतुलित होना चाहिए। निष्कर्षरूप स्वच्छ हवा के लिए समग्र दृष्टिकोण जरूरी इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य की परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे प्रदूषण का समस्या का अकेला समाधान नहीं हैं। स्वच्छ हवा के लिए निजी वाहनों के उत्सर्जन को कम करने के साथ-साथ सार्वजनिक बसों को मजबूत करना, पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए सुरक्षित रास्ते बनाना, बिजली उत्पादन को अधिक स्वच्छ करना और बैटरियों का जिम्मेदारी से पुनर्चक्रण करना आवश्यक है। वास्तविक परिवर्तन तब आएगा, जब नागरिकों को निजी वाहन खरीदने के बजाय सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन चुनने का विकल्प मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा से चलने वाली परिवहन व्यवस्था सुलभ तथा विश्वसनीय बनेगी। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को केवल वाहन उद्योग के विस्तार के रूप में नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर शहरी जीवन से जुड़ी व्यापक पहल के रूप में देखना होगा। स्वच्छ परिवहन का अर्थ केवल पेट्रोल—डीजल से बिजली की ओर बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है जिसमें यात्राएं सुविधाजनक हों, प्रदूषण कम हो, संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग हो और हर नागरिक को सुरक्षित आवागमन का अवसर मिले।

व्यापार समझौते की असली कसौटी:निर्यात वृद्धि और देशहित का संतुलन

और स्थिर बाजार पहुंच मिलती है, तो निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति बेहतर हो सकती है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अमेरिकी बाजार में विस्तार की संभावना महत्वपूर्ण है। इन उद्यमों को नए ऑर्डर मिलने से उत्पादन बढ़ सकता है, स्थानीय रस्तर पर रोजगार पैदा हो सकता है और छोटे शहरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। हालांकि, इसके लिए केवल उद्यमों में राहत पर्याप्त नहीं होगी। उत्पादों की गुणवत्ता, समय पर आपूर्ति, प्रमाणन, तकनीकी मानकों और परिवहन लागत पर भी ध्यान देना होगा। निर्यात बढ़ाने की रणनीति तभी प्रभावी होगी, जब भारतीय कंपनियां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन कर सकें और बाजार में लंबे

समय तक टिकने की क्षमता विकसित करें। व्यापार समझौता अवसर उपलब्ध करा सकता है, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए घरेलू उद्योगों को भी अपनी उत्पादकता और तकनीकी



दक्षता बढ़ानी होगी। शुल्क में राहत के साथ घरेलू उद्योगों की सुख्या भी जरूरी व्यापार वार्ता में आयात शुल्क एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। इससे घटने से वस्तुओं की लागत कम हो सकती है, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल सकते हैं और उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे माल तथा तकनीक तक पहुंच मिल सकती

अर्थव्यवस्थाओं की संरक्षणवादी नीतियों के बीच भारत—अमेरिका व्यापार वार्ता का महत्व और बढ़ जाता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में व्यापक संभावनाएं हैं, लेकिन उनके आर्थिक हित, घरेलू प्राथमिकताएं और बाजार संबंधी चिंताएं हमेशा एक जैसी नहीं होती। इसलिए बातचीत में अवसरों की पहचान के साथ—साथ संभावित संभावनाएं, लेकिन उनकी आवश्यक है। अमेरिकी बाजार तक पहुंच से बढ़ सकती है भारतीय निर्यातकों की संभावनाएं। अमेरिका का बड़ा उपभोक्ता बाजार भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। कपड़ा एवं पश्चिान, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, हस्तशिल्प और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी गतिविधियों में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति है। यदि प्रस्तावित समझौते से भारतीय उत्पादों को अधिक अनुकूल शुल्क व्यवस्था, पारदर्शी नियम

आवश्यक है। अमेरिकी बाजार तक पहुंच से बढ़ सकती है भारतीय निर्यातकों की संभावनाएं। अमेरिका का बड़ा उपभोक्ता बाजार भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। कपड़ा एवं पश्चिान, औषधि, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, हस्तशिल्प और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी गतिविधियों में भारतीय कंपनियों की उपस्थिति है। यदि प्रस्तावित समझौते से भारतीय उत्पादों को अधिक अनुकूल शुल्क व्यवस्था, पारदर्शी नियम

महंगाई के आंकड़ों से आगे, रसोई और रोजगार की चिंता समझें नीति-निर्माता

भारतार्थ खबर Bhaaratarth.com

महंगाई केवल अर्थव्यवस्था से जुड़ा आंकड़ा नहीं, बल्कि आम आदमी के जीवन, परिवार के बजट और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। जब खाद्य पदार्थों, ईंधन, परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका प्रभाव घर की रसोई से लेकर छोटे कारोबार और रोजगार के अवसरों तक दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में आर्थिक विकास की चर्चा के साथ यह देखना भी जरूरी है कि बढ़ती लागत का बोझ समाज के अलग-अलग वर्गों पर कितना पड़ रहा है और उसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सितंबर 2026 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में थोक मूल्य सूचकांक (व) आधारित महंगाई की वार्षिक दर बढ़कर 11.39 प्रतिशत हो गई, जबकि अग्रस्त में यह 9.92 प्रतिशत थी। ईंधन एवं बिजली, खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों की कीमतों में वृद्धि ने इस उछाल में योगदान दिया। विशेष रूप से ईंधन एवं बिजली विमूह में महंगाई की दर 25.85 प्रतिशत दर्ज की गई। ये आंकड़े बाजार में लागत के बढ़ते दबाव की ओर संकेत करते हैं। हालांकि, थोक

महंगाई और खुदरा महंगाई में अंतर है। थोक मूल्य सूचकांक उत्पादकों और थोक बाजार में कीमतों के बदलाव को दर्शाता है, जबकि आम उपभोक्ता पर वास्तविक प्रभाव खुदरा कीमतों, आय और खर्च की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। महंगाई का असली असर परिवार के बजट पर आम परिवार के लिए महंगाई का अर्थ पड़ सकता है, क्योंकि उनकी आय का बड़ा हिस्सा भोजन, आवास और अन्य अनिवार्य जरूरतों पर खर्च होता है। कीमतें बढ़ने पर वे मनोरंजन, कपड़े, शिक्षा से जुड़े अतिरिक्त खर्च या बचत में कटौती करने को मजबूर हो सकते हैं। मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहता। नियमित वेतन पाने वाले परिवारों के सामने बढ़ते खर्च और सीमित आय के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है।

इसलिए महंगाई का आकलन केवल औसत आंकड़ों से नहीं होना चाहिए। यह भी समझना होगा कि अलग-अलग आय वर्गों, ग्रामीण परिवारों, शहरी कामगारों और छोटे कारोबारियों पर कीमतों में वृद्धि का प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है। ईंधन की लागत से वस्तुओं की कीमतों तक ईंधन और बिजली की कीमतें अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। कृषि में सिंचाई, मशीनों के संचालन और माल ढुलाई की लागत बढ़ सकती है। उद्योगों को उत्पादन के लिए अधिक खर्च करना पड़ सकता है। परिवहन महंगा होने पर खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की अंतिम कीमतों पर भी दबाव पड़ सकता है। हालांकि, थोक बाजार में कीमतें बढ़ने का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक वस्तु की खुदरा कीमत उसी अनुपात में बढ़ेगी। उत्पादकों और व्यापारियों के लाभ, भंडारण लागत, प्रतिस्पर्धा, सरकारी करों तथा आपूर्ति शिक्षा से जुड़े अतिरिक्त खर्च या बचत में कटौती करने को मजबूर हो सकते हैं। मध्यम वर्ग भी इससे अछूता नहीं रहता। नियमित वेतन पाने वाले परिवारों के सामने बढ़ते खर्च और सीमित आय के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है।

कारणों की पहचान करें। यदि समस्या उत्पादन में कमी, परिवहन की बाधाओं या बाजार में आपूर्ति की अनियमितता से जुड़ी है, तो उसके समाधान के लिए लक्षित कदम उठाए जाने चाहिए। किसानों और छोटे



कारोबारियों की चुनौतियां महंगाई के प्रभाव को समझते समय किसानों और छोटे उद्यमियों की स्थिति भी ध्यान में रखनी चाहिए। किसानों के लिए बीज, उर्वरक, डीजल, बिजली और कृषि उपकरणों की लागत बढ़ना चिंता का विषय हो सकता है। यदि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो बढ़ती उत्पादन लागत उनकी आय पर दबाव डाल

सकती है। दूसरी ओर, खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने पर उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदना कठिन हो सकता है। इस स्थिति में कृषि उत्पादन, भंडारण, शीतगृह सुविधाओं, ग्रामीण सड़कों और बाजार तक पहुंच

है। रोजगार और आर्थिक विकास से जुड़ा प्रश्न महंगाई की चुनौती केवल उपभोग तक सीमित नहीं है। यदि उत्पादन लागत लगातार बढ़ती है, तो कुछ कारोबार अपने विस्तार, नई भर्तियों या निवेश संबंधी फैसलों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। दूसरी ओर, यदि बढ़ती कीमतों के साथ लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति कमजोर हो रही है, तो बाजार में मांग प्रभावित हो सकती है। हालांकि, रोजगार पर प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र की परिस्थितियों और आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करता है, इसे केवल महंगाई के एक आंकड़े से निर्धारित नहीं किया जा सकता। आर्थिक नीति का उद्देश्य सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने, परिवहन लागत कम करने, भंडारण और संबंधित संस्थाएं कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सामान्य बाजार गतिविधियों को बिना पर्याप्त जांच के दोषी ठहराने से बचना भी जरूरी है। कम आय वाले परिवारों और जरूरतमंद वर्गों के लिए लक्षित सहायता योजनाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। साथ ही, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने

बैंगलुरु, शुक्रवार , 16 अक्टूबर 2026

प्रादेशिक समाचार

Bhaarataarth.com

4

हारी सीट पर जीत का इतिहास रचें, जीती सीट बचाएं:बी.के. हरिप्रसाद ने कांग्रेस नेताओं को दिया एकजुटता का संदेश



भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
संवाददाता कानाराम प्रजापत
बैंगलुरु,15 अक्टूबर 2026।
कर्नाटक में आगामी विधान परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक तैयारियां तेज करने पर जोर दिया है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद ने पार्टी नेताओं की और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जिन सीटों पर पार्टी को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, वहां जीत हासिल करने के लिए संगठित प्रयास किए जाएं और मौजूदा सीटों पर अपना प्रभाव बनाए रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी सफलता केवल उम्मीदवारों

मजबूत करने पर जोर हरिप्रसाद ने कहा कि चुनाव केवल उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि यह पार्टी की संगठनात्मक क्षमता, कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता और मतदाताओं के विश्वास की भी परीक्षा है। उन्होंने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने, उनकी समस्याओं को सुनने तथा पार्टी की नीतियों और सरकार के कार्यों की जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल बैठकों आयोजित करने से चुनावी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी। इसके लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना, मतदाताओं तक व्यवस्थित ढंग से पहुंचना और प्रभावी कार्ययोजना के अनुसार अभियान चलाना आवश्यक है। उन्होंने पार्टी नेताओं से आपसी मतभेदों को किनारे रखकर साझा लक्ष्य के लिए काम करने की अपील की। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पुट्टन्ना के काम का उल्लेख बैंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का उल्लेख करते हुए हरिप्रसाद ने विधान परिषद सदस्य गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने विधायकों, जिला कांग्रेस अध्यक्षों, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों और अन्य पदाधिकारियों से अपनी जिम्मेदारियों का सक्रियता से निर्वहन करने की अपील की। बूथ स्तर तक संगठन

करने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों को पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ा बताते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवारों का मुकाबला करने के लिए एकजुटता पर बल दिया। आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी तैयारी हरिप्रसाद ने कहा कि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव भी होने हैं, इसलिए मौजूदा चुनाव पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करने और भविष्य की रणनीति तैयार करने का अवसर हैं। उन्होंने पिछले चुनावों के अनुभवों से सीख लेने और कमजोरियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि जीत संगठन को नई मजबूती देती है, जबकि हार अपनी कमियों का आकलन करने और सुधार करने का अवसर प्रदान करती है। इसलिए किसी भी चुनाव को हल्के में लेने की बजाय निरंतर तैयारी और सक्रिय जनसंपर्क पर ध्यान देना चाहिए। गोपीनाथन पलानीयपन बोलेकुकिरी चुनाव को छोटा न समझें बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीपी) के सचिव गोपीनाथन पलानीयपन ने कहा कि पार्टी को किसी भी चुनाव को छोटा या बड़ा मानकर नहीं चलना चाहिए। प्रत्येक चुनाव संगठन की क्षमता और जमीनी

सक्रियता की परीक्षा होता है। प्रभावी परिणामों के लिए ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से मतदाताओं के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने तथा चुनाव अभियान को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी कहा कि उम्मीदवारों की सफलता के लिए पार्टी की विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। कई वैरिष्ठ नेता और पदाधिकारी रहे मौजूद बैठक में राज्यसभा सदस्य संसूर अली खान, विधायक कोट्टूर मंजूनाथ, कुनिगल रंगनाथ और समर्थ शमनूर सहित विधान परिषद सदस्यों सीताराम, रामोजी गौड़ा और श्रीनिवास ने भाग लिया। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पराजित उम्मीदवारों, जिला एवं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों तथा विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। बैठक में दिए गए संदेश का मुख्य और संगठनात्मक एकजुटता, बूथ स्तर पर सक्रियता, मतदाताओं से सीधा संवाद और आगामी चुनावों के लिए समय रहते तैयारी करने पर रहा। अब इन निर्देशों को जमीनी स्तर पर किस तरह लागू किया जाता है, यह आगामी चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा।

बिहार के राघोपुर में नाव हादसे से हड़कंप, लापता लोगों की तलाश और बचाव पर जोर

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

वैशाली,15 अक्टूबर 2026। बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर क्षेत्र में नाव पलटने की घटना से चिंता का माहौल है। हादसे में कई लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है, जबकि प्रभावित लोगों की तलाश

सकता है। बचाव अभियान और प्रशासनिक कार्रवाई अहम ऐसी दुर्घटनाओं में स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा राहत दलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समय पर तलाश और बचाव कार्य शुरू करना, घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना तथा प्रभावित परिवारों तक



और राहत-बचाव प्रयासों को लेकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। हालांकि, मृतकों और लापता लोगों की संख्या तथा दुर्घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। नाव पलटने की घटना के बाद प्राथमिकता नदी में लापता लोगों का पता लगाने, प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने और हादसे से जुड़े तथ्यों का पता लगाने की है। नदी के बहाव, पानी की गहराई और अन्य स्थानीय परिस्थितियों के कारण बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण हो

जरूरी मदद पहुंचाना प्राथमिकता होती है। हादसे में कितने लोग सवार थे, कितने लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए और कितने लोग लापता हैं, इन सवालों के जवाब आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेंगे। दुर्घटना के कारणों का निष्पक्ष आकलन करने के लिए भी प्रशासनिक जांच महत्वपूर्ण होगी। नदी में नाव यात्रा की सुरक्षा फिर चर्चा में बिहार के अनेक नदी क्षेत्रों में नावों आवागमन का महत्वपूर्ण साधन हैं। खासकर उन इलाकों में, जहाँ

यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर, सपा के तीन विधायक भाजपा में शामिल

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
अमेठी,15 अक्टूबर 2026। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। अमेठी के गौरीगंज में बुधवार को आयोजित सदस्यता कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी (सपा) से जुड़े तीन विधायक राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और विनोद चतुर्वेदी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हो गए। उपलब्ध विवरण के अनुसार, कार्यक्रम में भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। इस घटनाक्रम को प्रदेश में दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच बदलते समीकरणों के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इसका वास्तविक चुनावी प्रभाव संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की स्थिति, स्थानीय मुद्दों और मतदाताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। तीन विधायकों के दल बदलने से बड़ी राजनीतिक चर्चा भाजपा में शामिल होने वाले तीनों विधायकों की अपनी-अपनी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक पहचान रही है। उनके दल बदलने से आगामी चुनाव से पहले स्थानीय राजनीतिक गतिविधियों में बदलाव की संभावना जताई जा रही

है। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक राकेश प्रताप सिंह के सपा नेतृत्व के साथ मतभेद पहले भी चर्चा में रहे हैं। उनके भाजपा में शामिल होने से अमेठी क्षेत्र के राजनीतिक समीकरणों पर नजर रहेगी। अभय सिंह अयोध्या जिले की गौसाईगंज विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने



वाले अभय सिंह का नाम राज्यसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान को लेकर चर्चा में आया था। उनके भाजपा में शामिल होने से इस क्षेत्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावना है। विनोद चतुर्वेदी जालौन जिले की कालपी विधानसभा सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी का भाजपा में जाना भी आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। उनके दल परिवर्तन का स्थानीय संगठन और चुनावी रणनीति

पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आगे स्पष्ट होगा। 2027 के चुनाव से पहले सियासी समीकरणों पर नजर उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में नेताओं के दल बदलने की घटनाएँ राजनीतिक दलों की रणनीति और संगठनात्मक तैयारियों को प्रभावित कर सकती हैं। भाजपा के लिए नए नेताओं का जुड़ना संगठन के विस्तार और संबंधित क्षेत्रों में राजनीतिक आधार मजबूत करने का अवसर हो सकता है। दूसरी ओर, सपा के सामने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में संगठन को मजबूत बनाए रखने और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने की चुनौती होगी। हालांकि, केवल विधायकों के पार्टी बदलने से चुनावी नतीजों का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय विकास के मुद्दे, जातीय और सामाजिक समीकरण तथा मतदाताओं का रुख भी चुनावी परिणामों को प्रभावित करेंगे। टिकट और स्थानीय जनसमर्थन के बनेगा अहम फैसला भाजपा में शामिल होने वाले विधायकों को आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट मिलेगा।

राशन लाभार्थियों को बड़ी राहत: ‘अन्ना सेवा’ ऐप से घर बैठे ई-केवाईसी, 20 अक्टूबर तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com
बैंगलुरु, 15 अक्टूबर 2026।
कर्नाटक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और 'अन्न भाग्य' योजना के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की प्रक्रिया आसान बनाने की दिशा में 'अन्ना सेवा' मोबाइल ऐप का दायरा पूरे राज्य में बढ़ाया जा रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार, यह ऐप अब राज्य के सभी जिलों के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थी आधार से जुड़ी फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा का उपयोग कर स्वयं ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और ई-गवर्नेंस विभाग के सहयोग से विकसित इस ऐप को खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रिजवान अरशद ने 1 अक्टूबर को लॉन्च

शेष जिलों के लाभार्थियों को भी ऐप के जरिए ई-केवाईसी पूरी करने की सुविधा दी जा रही है। राशन दुकानों की कतारों से मिलेगी राहत अब तक कई लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराने के लिए उचित मूल्य की राशन दुकानों या संबंधित सरकारी केंद्रों तक जाना पड़ता था। कामकाजी लोगों, विशेषकर उन लाभार्थियों को इससे परेशानी होती थी जो रोजगार के लिए अपने गांव से दूर शहरों और कस्बों में रहते हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए उन्हें काम से छुट्टी लेकर अपने गांव जाना पड़ सकता था। एक जगहों पर राशन दुकानों के बाहर लंबी कतारों में इंतजार भी करना पड़ता



लिए उन्हें काम से छुट्टी लेकर अपने गांव जाना पड़ सकता था। एक जगहों पर राशन दुकानों के बाहर लंबी कतारों में इंतजार भी करना पड़ता

था। 'अन्ना सेवा' ऐप के माध्यम से इस परेशानी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लाभार्थी गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर आधार-आधारित फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए अपनी ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं। इससे प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो सकती है और सरकारी केंद्रों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। 12 दिनों में 1.60 लाख से अधिक लाभार्थियों ने किया उपयोग विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 से 12 अक्टूबर के बीच शुरुआती आठ जिलों में कुल 1,60,267 लाभार्थियों ने ऐप का उपयोग करके ई-केवाईसी पूरी की। राज्यभर में ई-केवाईसी के लिए निर्धारित 2,67,64,276 लाभार्थियों में से 12 अक्टूबर तक 2,06,76,278 लोग यह प्रक्रिया पूरी कर चुके थे। इस प्रकार बड़ी संख्या में लाभार्थियों की ई-केवाईसी अभी

शेष थी। विभाग को उम्मीद है कि ऐप की सुविधा सभी जिलों में उपलब्ध होने से बाकी लाभार्थियों को प्रक्रिया पूरी करने में मदद मिलेगी। मंत्री रिजवान अरशद ने शेष लाभार्थियों से जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करने की अपील की है। विभागीय सूचना में ई-केवाईसी पूरी करने की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर बताई गई है। साथ ही, जिन लाभार्थियों ने एक वर्ष से अधिक समय पहले ई-केवाईसी कराई थी, उन्हें भी दोबारा प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे ऐप डाउनलोड करते समय उसके आधिकारिक नाम और प्रकाशक की पुष्टि करें तथा आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी जानकारी केवल अधिकृत माध्यम से ही साझा करें। समय-सीमा को देखते हुए शेष लाभार्थियों के लिए प्रक्रिया पूरी करना महत्वपूर्ण है।

भारतार्थ खबर Bhaarataarth.com

मुंबई,15 अक्टूबर 2026। भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 251.89 अंक यानी 0.34 प्रतिशत टूटकर 72,781.89 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 99.25 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 22,622.70 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा पर दबाव डाला। बाजार में गिरावट के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के शेयरों में मजबूती देखने को मिली। हालांकि, इस क्षेत्र की तेजी व्यापक बाजार को गिरावट से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के तिमाही नतीजों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेतकों और विदेशी निवेश के रुझान पर है। कच्चे तेल की तेजी ने बढ़ाई चिंता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे

तेल की कीमतें लगभग 106 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने की खबरों ने निवेशकों की चिंता बढ़ाई। होर्मुज शेरार बाजार में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। कारोबारी सत्र के अंत में बीएसई सेंसेक्स 251.89 अंक यानी 0.34 प्रतिशत टूटकर 72,781.89 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 में 99.25 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 22,622.70 अंक पर बंद हुआ। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने निवेशकों की धारणा पर दबाव डाला। बाजार में गिरावट के बीच सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के शेयरों में मजबूती देखने को मिली। हालांकि, इस क्षेत्र की तेजी व्यापक बाजार को गिरावट से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं रही। निवेशकों की नजर अब कंपनियों के तिमाही नतीजों, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकेतकों और विदेशी निवेश के रुझान पर है। कच्चे तेल की तेजी ने बढ़ाई चिंता अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कितने समय

तक जँची रहती हैं और घरेलू बाजार में उनका कितना असर दिखाई देता है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली से दबाव विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक अन्य संभावित कारण रही। वैश्विक ब्याज दरों, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव के बीच विदेशी निवेशक उमरते बाजारों में अपने निवेश की समीक्षा कर सकते हैं। विदेशी निवेशकों की ओर से बड़े पैमाने पर शेयरों की बिक्री होने पर बाजार में दबाव बढ़ सकता है। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी इस प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित कर सकती है। बाजार की आगे की दिशा समझने के लिए निवेश के प्रवाह से जुड़े आधिकारिक आँकड़ों पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। आईटी शेयरों ने दिखाई मजबूती बाजार के प्रमुख सूचकांकों में गिरावट के बावजूद आईटी क्षेत्र के शेयरों में अपेक्षाकृत मजबूती रही।